



एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन, 2017: एक समीक्षा

डॉ. अरुंधती शर्मा

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 21 देश 6-11 नवंबर, 2017 को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम के दा नांग में एकत्र हुए। वियतनाम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का ध्यान, "नई गतिशीलता पैदा करना- साझा भविष्य को सजोना" पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन के दौरान बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें 8 नवंबर को उनतीसवीं मंत्रिस्तरीय बैठक और 11 नवंबर को एपेक आर्थिक नेताओं की पच्चीसवीं बैठक शामिल है। 21 एपेक सदस्य-अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने एपी आर्थिक मामलों के नेताओं के बाद दा नांग घोषणा जारी की जिसकी अध्यक्षता वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग ने की। दा नांग घोषणा ने सहयोग के चार क्षेत्रों की पहचान की : क) सतत, अभिनव और समावेशी विकास; ख) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और संपर्कता; ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गतिशीलता और ; घ) खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि को प्राप्त करना।

शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह वैश्विक व्यापार की बढ़ती विपरीत परिस्थितियों के बीच हुआ, जो विशेष रूप से 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी' में व्यापार के मुद्दों पर ट्रम्प प्रशासन के तहत नीतिगत परिवर्तनों से उत्पन्न हुआ। हालांकि, इस बार व्यापार के खुलेपन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बताई गई स्थिति दिलचस्प है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने भाषण में, "भारत-प्रशांत के सभी राष्ट्रों के बीच मित्रता और वाणिज्य के संबंध को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नए सिरे से साझेदारी की पेशकश की," जबकि उसी समय में, अपनी 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी' का उल्लेख करते हुए निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के अंत में, नेताओं के बीच स्थितियों का एक मिलन था, जिसमें एक सर्वसम्मत दस्तावेज था, जो व्यापार और निवेश उदारीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण में विश्वास को पुनः स्थापित करता था।

अभिनय, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना

सतत, समावेशी और अभिनव विकास प्राप्त करने के लिए, नेताओं ने तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर अपनी स्थिति की पुष्टि की : क) गुणवत्ता विकास, संरचनात्मक सुधार और नवाचार ; ख) एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक समावेश; और ग) डिजिटल युग में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास।

पहला उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, नेताओं ने "व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 'मौद्रिक, राजकोषीय और संरचनात्मक नीतियों' के महत्व को रेखांकित किया। नेताओं ने एपेक क्षेत्र में आर्थिक

विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के प्रमुख प्रेरकों के रूप में नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। अन्य दो उद्देश्यों की खोज में, नेताओं ने डिजिटल युग में मानव संसाधन विकास पर 'एपेक कार्य एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक समावेश' और एपेक फ्रेमवर्क का समर्थन किया। यह मानते हुए कि "समावेश को बढ़ावा देना समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।" विकासशील और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर बड़े और छोटे, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध और प्रशांत के दो नों किनारों पर दूरगामी प्रभाव के साथ, "उन्नत आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक समावेश पर एपेक कार्य एजेंडा ने तीन प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डाला। ये हैं :

क) आर्थिक समावेशन से तात्पर्य समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक रूप से उनकी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सूचित किए जाने और आर्थिक अवसर तक पहुँच होने में समानता को दर्शाता है।

ख) वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और सस्ती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक उचित पहुंच है जो एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से वितरित लेनदेन, भुगतान, बचत, क्रेडिट और बीमा - की जरूरतों को पूरा करते हैं।

ग) सामाजिक समावेशन को उन लोगों के लिए समाज में भागीदारी की शर्तों में सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गरीबी और सामाजिक बहिष्कार और इक्विटी बढ़ाने के जोखिम में हैं।

तीन स्तंभों का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए उत्पादक रोजगार और अच्छा काम, समान काम के लिए समान वेतन, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं सहित वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना और शिक्षा, प्रशिक्षण और बाल देखभाल के अवसर, में सुधार करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है और विकलांग महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और व्यक्तियों के सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाता है।

यह स्वीकार करते हुए कि सभी अर्थव्यवस्थाओं को डिजिटल युग में मानव संसाधनों की मांगों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, डिजिटल युग में मानव संसाधन विकास पर एपेक फ्रेमवर्क ने तीन प्रमुख उद्देश्यों की पहचान की। ये हैं :

क) डिजिटल युग में मानव संसाधन विकास में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना ;

ख) तेजी से तकनीकी परिवर्तन के सामने मानव पूंजी के निर्माण में आम नीतिगत चुनौतियां को रेखांकित करना और ;

ग) पहचानना और सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्रवाई करना जहां एपेक का महत्व बढ़ सके।

इसकी प्राप्ति के लिए, नेताओं ने कुछ कार्य योजनाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया। इनमें शामिल हैं : क) श्रम बाजार पर भविष्य की प्रौद्योगिकियों के प्रभाव की जांच करने और भविष्य के कौशल और प्रशिक्षण के साथ-साथ उस क्षेत्र में नए सामाजिक जोखिमों की पहचान करने के लिए संयुक्त और क्षेत्रीय / एपीईसी अनुसंधान गतिविधियां जिन पर उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण ध्यान दिया जाना है; ख) क्षेत्रीय / एपेक नीति चर्चा में सरकार-व्यापी नीतियों के दृष्टिकोण की पहचान करना जो श्रम बाजार अनुकूलनशीलता, रोजगार और श्रमशक्ति की भागीदारी का समर्थन करते हैं, साथ ही शिक्षा और प्रशिक्षण के नए विकल्पों की खोज के साथ-साथ सामाजिक बीमा योजनाओं को प्रौद्योगिकी के नए रूपों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी। ग) कार्य के नए रूपों, आवश्यक कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, और बढ़े हुए डिजिटलाइजेशन से उत्पन्न सामाजिक सुरक्षा का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और संपर्कता

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के नए प्रेरकों के निर्माण की खोज में , घोषणा में चार उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है:

क) *खुले और मुक्त व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाना* : नेताओं ने एशिया- प्रशांत में खुले और मुक्त व्यापार को साकार करने के लिए बोगोर लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिस पर 1994 में इंडोनेशिया के बोगोर में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। व्यापार को अधिक समावेशी बनाने के लिए, नेताओं ने गैर-भेदभाव, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के महत्व को नोट किया। उन्होंने "अनुचित व्यापार प्रथाओं" का समाधान करने पर भी जोर दिया। नेताओं ने उपयुक्त विनियामक और नीतिगत ढांचे के माध्यम से इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता को साकार करने के महत्व पर भी बल दिया। इस संबंध में , नेताओं ने 'एपेक इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप' और 'सीमा पार से ई-कॉमर्स सुविधा' पर 'एपेक फ्रेमवर्क' को अपनाने का स्वागत किया।

इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एपेक रोडमैप ने डिजिटल अवसंरचना के विकास; अंतर संचालन को बढ़ावा देने; लागू घरेलू कानूनों और नियमों का सम्मान करते हुए डेटा और सूचना के मुक्त प्रवाह की सुविधा; समग्र सरकारी नीति ढांचे के विकास; विनियामक दृष्टिकोण के सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना; सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड एक्सेस; नवीनता; प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को अपनाने; और इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था की समावेशी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।

यह स्वीकार करते हुए कि ई- कॉमर्स एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रेरक बन गया है , सीमा- पार ई-कॉमर्स सुविधा पर एपेक फ्रेमवर्क ने पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य कानूनी और विनियामक दृष्टिकोण और उपायों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है जो क्षेत्र में सीमा पार ई-कॉमर्स की सुविधा के लिए व्यापार के अनुकूल और सुसंगत है । क्षमता निर्माण को बढ़ाता है ताकि एपेक अर्थव्यवस्था एमएसएमई को वैश्विक और क्षेत्रीय बाजारों में सीमा पार ई- कॉमर्स भागीदारी बढ़ाने में सहायता कर सके; मौजूदा एपेक कार्यक्रमों के बढ़ते कार्यान्वयन के माध्यम से सीमा पार डेटा गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत कर ता है; क्षेत्र में सीमा पार से कागज रहित व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और सीमा पार ई-कॉमर्स में उभरते और परस्पर प्रतिकूल मुद्दों को संबोधित करता है।

क) *एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीएपी)*: पिछले शिखर सम्मेलन की तरह, नेताओं ने एपीईसी के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के एजेंडे को मजबूत करने के लिए एफटीएपी की प्राप्ति के लिए "व्यापक और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

ख) *बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली* : नेताओं ने डब्ल्यूटीओ के पूरक द्विपक्षीय , क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौतों के साथ-साथ नियम-आधारित, मुक्त, खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को नोट किया।

ग) *क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय व्यापक और समावेशी समुदाय को बढ़ावा देना* : "2025 तक एक निर्बाध और व्यापक रूप से जुड़े हुए और एकीकृत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण" करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, नेताओं ने "अग्रिम नीति समन्वय, व्यापार सुविधा, संपर्कता, वित्तपोषण, और परस्पर जनसंपर्क हेतु" सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत किया । स्थायी आर्थिक विकास के लिए गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए , नेताओं ने निवेश और सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के मामले पर जोर दिया। नेताओं ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में बेहतर भागीदारी को सक्षम करने और जीवीसी में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और एमएसएमई की ऊर्ध्वधर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए विकासशील नीतियों पर भी ध्यान दिया। नेताओं ने आईएसआईएल, अल-कायदा और अन्य

आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न एपेक क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर और प्राकृतिक आपदाओं भी चिंता व्यक्त की।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गतिशीलता

एपेक शिखर सम्मेलन 2017 में नेताओं ने पांच विशिष्ट नीतिगत नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके एमएसएमई की क्षमता और नवाचार को मजबूत करने का संकल्प लिया:

क) विशेषकर महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए वित्त , प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की सुविधा सहित एमएसएमई की नवाचार क्षमता बढ़ाना।

ख) इंटरनेट और डिजिटल अवसंरचना ढांचे तक पहुंच में सुधार।

ग) डिजिटल क्षमताओं, प्रतिस्पर्धा और एमएसएमई के लचीलेपन को बढ़ाना।

घ) एमएसएमई के लिए व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा देने सहित एक सक्षम वातावरण बनाना।

ड) विनियामक ढांचे के साथ एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके स्टार्ट-अप का समर्थन करना जो एक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है , संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है , और स्टार्ट-अप नेटवर्क और साझेदारी का निर्माण करता है।

खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि

जलवायु परिवर्तन के अनुसार खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि को बढ़ाने के लिए , एपेक नेताओं ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की:

क) 2020 तक स्थायी एपीईसी खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करना। इस दिशा में , नेताओं ने "खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन बहु-वर्षीय कार्य योजना 2018-2020"को अपनाने का स्वागत किया। खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से , 2018-2020 से कार्य योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में नीतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और विद्यमान एपेक अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद क्षमता के स्तरों को स्पष्ट करने वाली गतिविधियों की स्थिति और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में खाद्य असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए एपेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावित प्रशिक्षण के अवसरों की पहचान और नई प्रथाओं को एकीकृत किया जाएगा।

ख) खाद्य व्यापार की लागत को कम करने के लिए क्षेत्रीय खाद्य बाजारों , खाद्य मानकों और आपूर्ति श्रृंखला संपर्कता में वृद्धि, बाजार पारदर्शिता में सुधार किया जाएगा और निर्यात और आयात करने वाले दोनों देशों को खाद्य मूल्य अस्थिरता के अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वृद्धि को मजबूत करने के लिए ग्रामीण-शहरी विकास संबंधी एपेक कार्य योजना को अपनाने का स्वागत करते हुए, नेताओं ने खाद्य उत्पादकों को घरेलू और वैश्विक खाद्य आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे, संभार तंत्र और कृषि उद्योग में निवेश के लिए नीति और विनियामक वातावरण में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया।। यह योजना एपेक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले तीन प्रमुख कार्यों को रेखांकित करती है। वे हैं : क) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्तापरक वृद्धि के लिए ग्रामीण- शहरी संपर्क पर ज्ञान को समेकित और प्रसारित करना ; ख) सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं और सीख को साझा करना ; और, (ग) ग्रामीण-शहरी सातत्यवादी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए नई नीतियों, साझेदारी, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करना।

ग) कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन में सतत खाद्य सुरक्षा और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना। यह भूमि, जंगल, समुद्र और जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन में सीमा-पार सहयोग और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

"नई गतिशीलता पैदा करना- साझा भविष्य को सजोना" की समग्र सोच के तहत आयोजित शिखर सम्मेलन ने 21 सदस्य देशों को मुक्त व्यापार के भविष्य आर्थिक विकास के नए चालक और क्षेत्र में आम चुनौतियों से निपटने में एपेक की भूमिका पर एक आम स्थिति पर चर्चा करने और तैयार करने का अवसर प्रदान किया। इस परिपेक्ष्य में दा नांग में एपेक शिखर सम्मेलन को सफल करार दिया जा सकता है। शिखर सम्मेलन मुक्त और खुले व्यापार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में 21 नेताओं के लिए एक लिटमस टेस्ट था। घोषणा में एक अलग अनुच्छेद में अनुचित प्रथाओं 'को रोकने के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है जो मुक्त और खुले व्यापार और निवेश को प्रतिबंधित करते हैं, और विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अनुरूप गैर- भेदभाव, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत का पालन करते हैं। यह तथ्य कि एपेक के सभी 21 सदस्य देशों द्वारा दा नांग घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया था, यह दर्शाता है कि मुक्त व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए उनकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

**

* डॉ. अरुंधती शर्मा, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्यक्षता हैं

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।

पादटिप्पणियां :

i "THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS' MEETING", Da Nang, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)

ii The White House, Office of the Press Secretary, "Remarks by President Trump at APEC CEO Summit, Da Nang, Vietnam", नवम्बर 10, 2017, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/11/10/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam> (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)

iii "THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS' MEETING", Da Nang, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)

iv "ANNEX A: APEC ACTION AGENDA ON ADVANCING ECONOMIC, FINANCIAL AND SOCIAL INCLUSION IN THE APEC REGION", APEC Economic Leaders' Meeting, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm/Annex-A (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)

- v “ANNEX A: APEC ACTION AGENDA ON ADVANCING ECONOMIC, FINANCIAL AND SOCIAL INCLUSION IN THE APEC REGION”, APEC Economic Leaders’ Meeting, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm/Annex-A (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- vi “ANNEX B: APEC FRAMEWORK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE”, APEC Economic Leaders’ Meeting, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm/Annex-B (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- vii “ANNEX B: APEC FRAMEWORK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE”, APEC Economic Leaders’ Meeting, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm/Annex-B (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- viii “THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS’ MEETING”, Da Nang, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- ix “APEC Internet and Digital Economy Roadmap”,
http://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17_csom_006.pdf (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- x “ANNEX A: APEC CROSS-BORDER E-COMMERCE FACILITATION FRAMEWORK”, APEC Ministerial Meeting, नवम्बर 8, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/2017/2017_amm/Annex-A (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- xi “THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS’ MEETING”, Da Nang, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- xii “THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS’ MEETING”, Da Nang, नवम्बर 11, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- xiii “ANNEX C: FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE MULTI-YEAR ACTION PLAN (MYAP) 2018-2020”, APEC Ministerial Meeting, नवम्बर 8, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/2017/2017_amm/Annex-C (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)
- xiv “ANNEX D: ACTION PLAN ON RURAL-URBAN DEVELOPMENT TO STRENGTHEN FOOD SECURITY AND QUALITY GROWTH”, APEC Ministerial Meeting, नवम्बर 8, 2017, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/2017/2017_amm/Annex-D (नवम्बर 20, 2017 को अभिगम्य)